जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

कोटा

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

फोनः- 2386031, 2386032 फैक्सः- 0744-2386033 वर्षः 51 संख्याः 4 प्रभात कोटा, गुरुवार 16 अक्टूबर, 2025 कोटा/24/2012-14 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

जदयू ने भाजपा को चुनौती/धमकी दी कि नीतीश को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करें अन्यथा ....

जदयू की अप्रत्यक्ष धमकी यह है कि अगर चुनाव के नतीजों तक का इन्तजार करेगी भाजपा तो उस समय तो सभी स्वतंत्र होंगे नई परिस्थितियों में नए समीकरण ढूंढने के लिये

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

- यह उल्लेखनीय है कि जदयू ने यह धमकी देने के लिए शायद राजनीतिक कारणों से प्रेस कॉन्फ्रेंस का रास्ता नहीं चुना है।
- पर जदयू के खेमे में इस मुद्दे पर कई सप्ताह से बहस छिड़ी हुई है कि भाजपा सुनियोजित तरीके से काफी अरसे से नीतीश कुमार को कमज़ोर करना चाहती है।
- यह भी महसूस किया जा रहा है कि भाजपा में काफी हिचकिचाहट है नीतीश को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने के बारे में।
- जदयू के कार्यकर्ता और नेता यह मानते हैं कि भाजपा का प्रयत्न है कि एनडीए के अन्य छोटे घटकों को, नीतीश को कमज़ोर करके पनपाया जाये।

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर। बिहार में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के भीतर की खामोशी बुधवार को उस समय और गहरा गई, जब जनता दल (यूनाइटेड) जेडीयू ने अपने बड़े सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को खुली चुनौती देते हुए कहा कि वह नीतीश कुमार को एनडीए का मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करे।

जेडीयू नेताओं ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हाशिये पर धकेलने और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के नेता चिराग पासवान जैसे अन्य सहयोगियों को टिकट वितरण में बढ़ावा देने की सुनियोजित कोशिश कर रही है।

पार्टी के सूत्रों ने बताया कि हालांकि जेडीयू ने यह मांग औपचारिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं उठाई, लेकिन भाजपा के बढ़ते दबदबे को लेकर पार्टी के भीतर कई हफ्तों से यह चर्चा चल रही थी। ताज़ा विवाद उस समय भड़का, जब भाजपा नीतीश कुमार को बिहार चुनाव अभियान में मुख्यमंत्री पद का निर्विवाद चेहरा घोषित करने की अनिच्छुक नज़र आई।

जेडीयू के वरिष्ठ एमएलसी और प्रवक्ता नीरज कुमार ने तीखे शब्दों में कहा, "भाजपा यह तय नहीं कर सकती कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। हमारे लिए यह सवाल बेमानी है, क्योंकि हम कई बार दोहरा चुके हैं कि नीतीश कुमार ही राज्य के निर्विवाद नेता हैं। अपने संन्यास या उत्तराधिकारी के बारे में फैसला केवल वही करेंगे।"

नीरज कुमार के ये बयान इस बात की ओर इशारा करते हैं कि जेडीयू में भाजपा की हाल की चुनावी रणनीतियों को लेकर नाराज़गी बढ़ रही है, जिन्हें नीतीश कुमार को दरकिनार करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।

भाजपा की छोटी पार्टियों से नज़दीकी और टिकट वितरण पर उसके नियंत्रण ने जेडीयू नेताओं में असंतोष

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जयपुर सेशन कोर्ट में बम की सूचना से अफरातफरी मची

जयपुर, 15 अक्टूबर। बनीपार्क स्थित जयपुर सेशन कोर्ट में बुधवार सुबह बम होने की सूचना से हड़कम्प मच गया और अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कोर्ट परिसर में सर्च अभियान शुरु किया, जिसमें बम निरोध दस्ता और डॉग स्क्वॉड टीम ने पूरी बिल्डिंग को खाली करवाते हुए चप्पे-चप्पे की तलाशी ली। पुलिस के सर्च अभियान

- बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वॉड टीम ने कोर्ट परिसर खाली कराके चप्पे-चप्पे की तलाशी ली।

कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिलने पर प्रशासन ने राहत की सांस ली।

पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि बुधवार सुबह सेशन कोर्ट परिसर में स्थित चौथे माले की पोक्सो कोर्ट को एक ईमेल आया, जिसमें लिखा था कि कोर्ट परिसर में बम लगाया हुआ है। कोर्ट रीडर ने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को इसकी जानकारी दी। इसके बाद सभी टीमें मौके पर पहुंचीं और कोर्ट परिसर को खाली कराया गया। बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉड की टीमें मौके पर पहुंचीं और कोर्ट परिसर की कोने-कोने की जांच की। इस दौरान अतिरिक्त

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नीतीश ने पासवान से पांच सीटें वापस खींच लीं

नीतीश ने इन पांचों सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिये और इन सीटों पर बातचीत का स्कोप ही खत्म कर दिया

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

- नीतीश इस बात से परेशान व कुपित थे कि सीट शेयरिंग समझौते के तहत चिराग पासवान को वो सीटें अलॉट की गई थीं जिन पर जदयू के उम्मीदवार पिछले चुनावों में जीत कर आए थे।
- यह पांच सीटें हैंः मोरवा सोनबरसा, राजगीर, गायघाट व मटिहानी।
- गत लोकसभा चुनावों में चिराग पासवान की पार्टी ने पांच सीटों पर चुनाव लड़ा था और पांचों में जीतकर आई थी, अतः इस बार चिराग सीटों के बंटवारे पर भारी दबाव बना सके थे और उन सीटों पर भी दावा ठोक दिया था जो परंपरागत रुप से जदयू की मानी जाती थीं।

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर। अपने सहयोगी दल भाजपा द्वारा उम्मीदवारों की सूची जारी करने के एक दिन बाद, नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जेडीयू ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने 57 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। मौजूदा सरकार के पांच मंत्रियों को फिर से टिकट मिला है। तीन बाहुबली, जिनमें अनंत कुमार सिंह भी शामिल हैं, जदयू की पहली सूची में हैं। इस सूची में चार महिला उम्मीदवारों को भी जगह दी गई है।

जेडीयू को वे पांच सीटें मिल गई हैं, जिन पर पासवान दावा कर रहे थे। बताया जाता है कि जेडीयू के कब्जे वाली सीटें चिराग पासवान की पार्टी को दिए जाने से नीतीश कुमार नाराज थे।

पहली सूची में शामिल पांच मंत्री तथा उन्हें दी गई सीटें हैं – ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार (नालंदा), जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी (सरायरंजन), सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारी (कल्याणपुर), सामाजिक कल्याण मंत्री मदन सहनी (बहादुरपुर) और मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सादा (सोनबरसा)।

जेडीयू और भाजपा 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा की 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी सीटें चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और उपेन्द्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा के बीच बांटी गई हैं। पिछले साल लोकसभा चुनाव में 5 में से 5 सीटें जीतने वाले चिराग पासवान ने इस बार सीट बंटवारे में कडा रुख अपनाया है। वर्ष 2020 के चुनाव में उन्होंने अकेले चुनाव लड़ा था, जिससे कई सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों को नुकसान हुआ था।

कम से कम पांच सीटों – मोरवा, सोनबरसा, राजगीर, गायघाट और मटिहानी, जिन पर जेडीयू ने उम्मीदवार घोषित किए हैं, के पहले चिराग पासवान के हिस्से में जाने की संभावना थी। सूत्रों के अनुसार, इसे लेकर नीतीश कुमार नाखुश थे और उन्होंने जोर दिया कि ये सीटें जेडीयू के पास रहनी चाहिए। जेडीयू ने आज इन सभी सीटों के लिये अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। 2020 के चुनाव में मोरवा और गायघाट सीटें आरजेडी ने जीती थीं, जबकि राजगीर और सोनबरसा पर जेडीयू का कब्जा था। मटिहानी सीट से लोक जनशक्ति पार्टी के राजकुमार सिंह विजयी हुए थे, लेकिन बाद में उन्होंने जेडीयू जॉइन कर ली थी।

वांगचुक की पत्नी ने "हेबियस कॉर्पस" याचिका में संशोधन किया

यह संशोधन वांगचुक के वकील कपिल सिब्बल ने समझाकर करवाया

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

- सिब्बल ने कहा कि वांगचुक ने अपनी हिरासत के संबंध में कुछ नोट्स बनाए थे जो वे अपने वकील को देना चाहते थे पर सरकार ने इस पर रोक लगा रखी थी।
- कपिल सिब्बल का तर्क था कि वांगचुक को ये नोट्स अपने वकील को देने का अधिकार है और इन नोट्स से केस मजबूत होगा।
- सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने नोट्स शेयर किए जाने पर सहमति दी पर कहा कि इन नोट्स से केस में देरी होती है तो उसका जिम्मेवार सरकार को नहीं ठहराया जाना चाहिए।

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को याचिकाकर्ता गीतांजलि जे. अंगमो को अपने पति सोनम वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एन एस ए) के तहत की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली "हैबियस कॉर्पस" (बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका) में संशोधन करने की अनुमति दे दी।

सर्वोच्च न्यायालय की जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन.वी. अंजनिया की पीठ ने इस मामले की अगली सुनवाई 29 अक्टूबर, बुधवार को तय की है।

दो दिन पहले केन्द्र सरकार ने अंगमो को वांगचुक की गिरफ्तारी के आधार (ग्राउन्ड्स ऑफ डिटैंशन) उपलब्ध कराए थे।

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, जो अंगमो की ओर से पेश हुए, ने अदालत से याचिका में संशोधन करने की अनुमति मांगी, ताकि सरकार द्वारा दिए गए गिरफ्तारी के आधारों को उचित रूप से चुनौती दी जा सके।

उन्होंने स्पष्ट किया कि वांगचुक को अपने नोट्स पत्नी के साथ साझा करने की अनुमति नहीं दी गई है। उन्होंने कहा, "उन्होंने (वांगचुक) अपनी गिरफ्तारी को लेकर कुछ नोट्स बनाए हैं जिन्हें वे अपने वकील तक पहुंचाना चाहते थे। जो भी नोट्स वे तैयार करते हैं, उन्हें अपने वकील की सहायता लेने का अधिकार है। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि वे नोट्स वकील तक पहुंच सकें।"

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो केन्द्र सरकार की ओर से पेश हुए, ने कहा कि उन्हें नोट्स याचिकाकर्ता के साथ साझा करने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि गिरफ्तारी के आधार प्रदान करने में हुई

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भजन गायिका मैथिली ठाकुर को भाजपा ने टिकट दिया

पटना, 15 अक्टूबर। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बुधवार को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 12 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है।

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरूण सिंह ने आज 12 उम्मीदवारों की

- भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने 12 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की जिसमें मैथिली ठाकुर को अलीनगर से प्रत्याशी बनाया गया है।

दूसरी सूची जारी की। सूची के अनुसार, लोक गायिका मैथिली ठाकुर को अलीनगर का प्रत्याशी बनाया गया है। मैथिली ठाकुर कल ही भाजपा में शामिल हुई हैं। बक्सर से पूर्व भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए कृत्रिम वर्षा कराई जा सकती है दिल्ली में

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए लागू किए गए ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत यह घोषणा की

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

- इस बार दीवाली से एक सप्ताह पहले ही जीआरएपी लागू कर दिया गया है, इससे संकेत मिलता है कि सर्दियों में दिल्ली में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर तक बढ़ सकता है।
- दिल्ली सरकार गत तीन माह से "क्लाउड सीडिंग" कराने की योजना बना रही है, पहले 4 से 11 जुलाई के बीच और फिर 30 अगस्त से 10 सितम्बर के बीच का समय तय किया गया था। पर तब मानसून की सक्रियता के कारण क्लाउड सीडिंग टाल दी गई।

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर। क्लाउड सीडिंग, जीआरएपी और ग्रीन क्रैकर (इको फ्रैंडली पटाखे) ये आदेश भले ही अलग-अलग लगें, लेकिन लक्ष्य एक ही है – दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करना।

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बुधवार को घोषणा की कि अगर मौसम की स्थिति अनुकूल रही तो सरकार आने वाले दो से तीन दिनों में क्लाउड सीडिंग या कृत्रिम वर्षा का प्रयोग करेगी। यह फैसला उस दिन के बाद आया जब वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान के पहले चरण के तहत प्रतिबंध लागू किए, क्योंकि दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एयर क्वालिटी इंडैक्स-एक्यूआई) 200 के पार चला गया था।

दीवाली से एक हफ्ते पहले जीआरएपी का लागू होना इस बात का संकेत है कि सर्दियों में दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खतरनाक हो सकता है।

इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ग्रीन क्रैकर की बिक्री और उपयोग की अनुमति दी, ताकि प्रदूषण नियंत्रण और दीवाली उत्सव के बीच संतुलन बनाया जा सके।

सिरसा ने बताया कि क्लाउड सीडिंग के लिए पायलट ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा, अगर अगले दो से तीन दिनों में मौसम अनुकूल रहा तो आईएमडी की मंजूरी के बाद तीन घंटे तक क्लाउड सीडिंग की जाएगी।

उन्होंने कहा, हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि सड़कों पर पुरानी गाड़ियां होने के बावजूद, इस साल हमें सबसे ज़्यादा दिनों तक साफ आसमान देखने को मिला।

दिल्ली सरकार पिछले तीन महीनों से कृत्रिम वर्षा कराने की योजना बना रही थी। शुरुआत में योजना थी कि 4 से 11 जुलाई के बीच क्लाउड सीडिंग की जाए, लेकिन मानसून के दौरान जब प्रदूषण का स्तर कम होता है, तब कृत्रिम वर्षा कराने के विचार की आलोचना हुई। हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि क्लाउड सीडिंग के लिए मानसूनी बादलों की आवश्यकता होती है।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे की सिफारिशों के बाद यह योजना आगे बढ़ाई गई और 30 अगस्त से 10 सितंबर के बीच का समय तय किया गया।

क्लाउड सीडिंग एक प्रक्रिया है जिसमें बादलों में सिल्वर आयोडाइड और ड्राई आइस जैसी विशेष सामग्रियाँ डाली जाती हैं ताकि कृत्रिम रूप से वर्षा या हिमपात कराया जा सके। इसका उपयोग पानी की कमी, कम हिमपात, या ओले और धुंध कम

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

श्रीलंका की प्र.मंत्री आज भारत में

नयी दिल्ली, 15 अक्टूबर। श्रीलंका की प्रधानमंत्री डॉ. हरिणी अमरसूर्या गुरूवार को तीन दिन की भारत यात्रा आयेंगी। पदभार ग्रहण करने के बाद उनकी यह पहली भारत यात्रा है। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को यहां बताया कि श्रीलंकाई प्रधानमंत्री भारतीय

- श्रीलंका की प्र.मंत्री डॉ. हरिणी अमरसूर्या तीन दिन के लिए भारत आयी हैं। पद ग्रहण के बाद वे पहली बार भारत आयी हैं।

नेताओं से मुलाकात करेंगी और उनके साथ आपसी हितों के द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगी।

श्रीलंकाई प्रधानमंत्री यहां एक निजी टेलीविजन चैनल और चिंतन रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आयोजित सम्मेलन में मुख्य भाषण देंगी। शिक्षा मंत्री की भी जिम्मेदारी संभाल रही डॉ.

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ब्रिक्स ट्रंप की अनिद्रा का भारी कारण क्यों बनता जा रहा है

ट्रंप जितने जोर शोर से टैरिफ की धमकियां देकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लेनदेन के लिये डॉलर को ही माध्यम बनाना चाहते हैं, डॉलर उतना ही कमज़ोर होता है

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

- ट्रंप जितनी धमकियां देते हैं उतना ही ब्रिक्स के घटक और अन्य देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डॉलर का एकाधिकार खत्म करना चाहते हैं।
- ट्रंप ने यह भी दंभपूर्वक कहा कि जैसे ही उन्होंने टैरिफ लगाने की धमकियां दीं ब्रिक्स की सदस्यता घटने लगी।
- उनका यह कथन पूर्णतया असत्य और काल्पनिक है। ब्रिक्स की सदस्य संख्या तो और बढ़ी है, तथा कई नए उभरते देशों ने सदस्यता लेने की इच्छा जाहिर की है।
- ब्रिक्स की सफलता से आशंकित ट्रंप व अमेरिका दोनों असुरक्षा की भावना से ग्रस्त हो रहे हैं, और यही ट्रंप की अनिद्रा का कारण है।

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप एक बार फिर अपने पुराने अंदाज़ में लौट आए हैं। ब्रिक्स समूह के खिलाफ उनका हालिया बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि वह "डॉलर पर बहुत मज़बूत" हैं और "जो भी देश डॉलर में लेन-देन करना चाहता है, उसे उन देशों पर बढ़त मिलेगी, जो ऐसा नहीं करते।" यह इस बात का संकेत हैं कि ब्रिक्स समूह की बढ़ती ताकत और प्रभाव को लेकर ट्रंप चिंतित हैं।

अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हावियर मिलेई के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान ट्रंप ने दुनिया को यही संदेश दिया। उन्होंने कहा, "जो भी ब्रिक्स में रहना चाहता है, वह रहे, लेकिन हम उसके देश पर टैरिफ लगाएंगे। सब बाहर निकल गए हैं, सारे देश ब्रिक्स छोड़ रहे हैं।"

एक स्तर पर ट्रंप के ये बयान उनकी जानी-पहचानी रणनीति का हिस्सा हैं, जिसमें वे व्यापारिक दबाव और टैरिफ को कूटनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ, उनकी लगातार और तीखी टिप्पणियाँ यह दिखाती हैं कि वे ब्रिक्स को सिर्फ एक आर्थिक गठबंधन नहीं, बल्कि अमेरिकी आर्थिक वर्चस्व के लिए अस्तित्व से जुड़ी चुनौती के रूप में देखते हैं। ब्रिक्स को "डॉलर पर हमला" बताना उनके लिए बहुत मायने रखता है, इसका मतलब है कि वे इस समूह के "डीडॉलराइज़ेशन" (डॉलर पर निर्भरता घटाने) के प्रयासों को सीधा खतरा मानते हैं।

इस कहानी में ट्रंप की बयानबाजी चिंताजनक है। वे बार-बार यह दावा दोहराते हैं कि "मेरी टैरिफ लगाने की धमकी के कारण सब देश ब्रिक्स से बाहर निकल गए," जबकि सच्चाई यह है कि ब्रिक्स का विस्तार हुआ है। उन्होंने यह तक कहा कि "अगर मैं चुनाव नहीं जीतता, तो आपके पास डॉलर अब आपकी मुद्रा के रुप में नहीं होता।" यह बयान दिखाता है कि ट्रंप डॉलर को अपनी निजी उपलब्धि की तरह देखते हैं, मानो डॉलर की ताकत उनकी जीत पर निर्भर हो। मौद्रिक नेतृत्व का यह निजीकरण एक गहरी चिंता का संकेत देता है कि दुनिया अमेरिका की आर्थिक कक्षा (ऑरबिट) से फिसल रही है।

उनके बयान का समय भी ध्यान देने योग्य है। हाल के महीनों में दर्जनों देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने में दिलचस्पी दिखाई है, खासकर ग्लोबल साउथ के देशों ने, जो पश्चिमी आर्थिक दबदबे से थक चुके हैं। यह समूह अब डॉलर से स्वतंत्र एक व्यापार व्यवस्था पर विचार कर रहा है, स्थानीय मुद्राओं या साझा डिजिटल इकाई के आधार पर। इससे अमेरिका की आर्थिक नीतियों और प्रतिबंधों का असर कम हो सकता है। लेकिन ट्रंप इसे एक आर्थिक बदलाव के बजाय अमेरिका के खिलाफ साजिश के रूप में देखते हैं।

अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हावियर मिलेई, जो खुद डॉलर समर्थक माने जाते हैं, के साथ मुलाकात के दौरान ट्रंप ने खुद को डॉलर के रक्षक के रूप में पेश किया। उन्होंने अपनी मज़बूती और टैरिफ नीति का ज़ोरदार बखान किया। परंतु ऐसा करते हुए उन्होंने अपनी असुरक्षा भी उजागर कर दी। एक आत्मविश्वासी महाशक्ति को दुनिया को बार-बार अपनी ताकत याद दिलाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ट्रंप द्वारा टैरिफ की धमकियों को बार-बार दोहराना नीति कम और प्रभाव में कमी से चिंतित एक नेता की चेतावनी ज्यादा लगती है। ट्रंप ने बार-बार कहा है कि, "मैंने ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा रखने वाले हर देश से कहा है कि, कोई बात नहीं, लेकिन हम आपके देश पर टैरिफ लगाएंगे।"

उनके बयान ऐसे समय आए हैं, जब ब्रिक्स देशों ने भी अंधाधुंध बढ़ते टैरिफ़ और व्यापार को हथियार बनाने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दिल्ली में "ग्रीन" पटाखों से मनेगी दीवाली

नयी दिल्ली, 15 अक्टूबर। उच्चतम न्यायालय ने दीपावली के त्योहार के दौरान 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच दिल्ली-एनसीआर में हरित पटाखों की बिक्री और उसे फोड़ने

- सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में 18 से 21 अक्टूबर तक "ग्रीन" पटाखे चलाने की अनुमति दी है।

की बुधवार को अनुमति दी।

मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अन्य की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया।

पीठ ने कहा, हमें एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा। हरियाणा के 22 जिलों में से 14 जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आते हैं। अदालत ने यह

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)